C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XXI, Tenth Session, 2016/1938 (Saka)
No. 13, Friday, December 02, 2016/Agrahayana 11, 1938 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
REFERENCE BY THE SPEAKER	
32nd Anniversary of the Bhopal Gas Tragedy	5
SUBMISSION BY MEMBER	
Re: Deployment of Army personnel around some Toll Plazas in West Bengal	6-10
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 241 to 247	11-65
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 248 to 260	66-218
Unstarred Question Nos. 2761 to 2990	219-618

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 620-627

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE
6th to 8th Reports 628

STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL
24th Report 629

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE
127th to 130th Reports 629

STATEMENT BY MINISTER
Status of implementation of the recommendations contained in the 71st and 88th Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on the`Functioning of Central Government Health Scheme (CGHS)', pertaining to the Ministry of Health and Family Welfare

Shri Jagat Prakash Nadda 630

OBSERVATION BY THE SPEAKER
Extension of time to inquiry committee to inquire into the improper conduct of Shri Bhagwant Mann, MP 631

BUSINESS OF THE HOUSE 632-638

<u>ANNEXURE – I</u>

Member-wise Index to Starred Questions 651

Member-wise Index to Unstarred Questions 652-657

<u>ANNEXURE – II</u>

Ministry-wise Index to Starred Questions 658

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 659

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, December 02, 2016/Agrahayana 11, 1938 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

REFERENCE BY THE SPEAKER

32nd Anniversary of the Bhopal Gas Tragedy

माननीय अध्यक्ष : जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल 3 दिसम्बर 2016 को भोपाल गैस त्रासदी की 32वीं बरसी है। इसी दिन वर्ष 1984 में विश्व की सबसे भयावह दुर्घटना हुई थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस तथा अन्य विषाक्त गैसों के रिसाव ने भीषण तबाही मचाई थी। इसके परिणामस्वरूप हजारों लोग मारे गए थे, अन्य कई हजार लोगों ने दुष्परिणाम झेले थे और आज भी झेल रहे हैं। इस घटना के विध्वंसक परिणाम इतने घातक थे कि उसके बाद पैदा होने वाले अनेक शिशु भी विभिन्न रोगों से पीड़ित पाए गए।

यह सभा इस त्रासदी के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना एवं अपने समर्थन की पुनः पुष्टि करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी।

11.02 hours

(The Members then stood in silence for short while.)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक विनती करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आप बाद में बोलिएगा। सुदीप जी को बोलने दीजिए।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : माननीय अध्यक्ष जी, मेरी विनती है, आज आपने जिस से भोपाल गैस पीड़ितों के लिए श्रद्धांजलि दी है, वैसे ही लाइन में खड़े होने पर 100 लोग मर गए हैं, उनके लिए भी श्रद्धांजलि होनी चाहिए।…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Sudip ji, do you not want to say anything?

… (*Interruptions*)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना): माननीय अध्यक्ष जी, खड़गे जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में कहा है।…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I have not allowed that.

… (*Interruptions*)

11.04 hours

SUBMISSION BY MEMBER
Re: Deployment of Army personnel around some Toll Plazas in West Bengal

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, yesterday in the afternoon, it was suddenly observed in West Bengal that the Army has taken over most of the toll plazas of the city of Kolkata and West Bengal. When the hon. Chief Minister enquired, she found that no permission was sought from the Secretariat of the West Bengal Government. *'Nabanna'*, is the name of the Secretariat of the West Bengal which is just attached to the Vidyasagar Toll Plaza. Just adjacent to this Toll Plaza, Army was deployed. Army was deployed in 19 places of the State of West Bengal. When clarifications were sought for, they said that it was a routine programme that they were launching. We cannot understand as to what the Army has to do for this. If such operation is to be made, then it should be communicated from the Ministry. The Defence Ministry will tell the State Government and they will come to the rescue. It is a fantastic situation going on. Army has declared today in the morning their authority by saying that they are

making the routine exercise in all the North Eastern States -- Manipur, Assam, Arunachal, Nagaland, Meghalaya, Tripura, Mizoram and West Bengal. Even they do not have the idea that West Bengal does not fall under the jurisdiction of the North-Eastern region.

The people of the country have the highest faith in the Army. They fight for the country. They give their lives for the country but why they are being used for this purpose? At some points they are collecting toll. We have a video showing this. I handed over a pen drive yesterday to the hon. President of India. I had reported to him also. Kumari Mamata Banerjee is sitting on a *dharna* inside her Chamber at *'Nabanna'*. We would request the hon. Defence Minister to immediately withdraw Army from there and if any such exercise is to be carried out, Government to Government negotiation should be there and then only the decision is to be taken. Otherwise, it will be difficult for the Ministry to convince us for the act. We will take it that motivation is behind all this and the federal structure is going to be challenged.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Madam, I would like to support him.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : इस पर सब नहीं बोलेंगे।

…(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : You may listen to us first and then let him reply.… (*Interruptions*) This is not the way.… (*Interruptions*)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्ष और सुदीप बन्दोपाध्याय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि …(व्यवधान) भारत की आर्मी, सेना, फौज को राजनीति में मत घसीटिए। …(व्यवधान) भारत की सेना भारत की सुरक्षा कर रही है, भारत के लोकतंत्र की सुरक्षा कर रही है। …(व्यवधान) हम उसका सम्मान करते हैं, गौरव करते हैं। …(व्यवधान) जो कुछ पश्चिम बंगाल, कोलकाता और बाकी पूर्वांचल में किया है, वह रूटीन एक्सरसाइज है। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि रक्षा मंत्री जी सदन में मौजूद हैं। …(व्यवधान) वे इस बारे में पूरा जवाब देंगे। …(व्यवधान) लेकिन भारत की सेना को राजनीति में घसीटना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। …(व्यवधान) यह सरासर गलत है।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत की सेना के बारे में आप बाहर सवाल करो और अंदर बवाल करो, तो यह ठीक नहीं है। …(व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री मनोहर पर्रिकर): अध्यक्ष महोदया, आज एक राज्य की मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से भारतीय सेना के बारे में कहा है, उससे मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। …(व्यवधान) मुझे सदन को इस बारे में कहना है कि यह आर्मी की एक रूटीन एक्सरसाइज है, जो पिछले कई वर्षों से जारी है। …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please listen to him. आप उनकी बात पूरी सुनिए।

… (*Interruptions*)

SHRI ANANTHKUMAR: Madam, they should listen to the statement being made by the hon. Minister.… (*Interruptions*)

श्री मनोहर पर्रिकर : पिछले वर्ष भी यह एक्सरसाइज 19 और 21 नवम्बर, 2015 को हुई थी। …(व्यवधान) तकरीबन पिछले 15-20 सालों से यह एक्सरसाइज चालू है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बोलते जाइये।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Kakoli ji, this is not fair.

श्री मनोहर पर्रिकर: अध्यक्ष महोदया, इस बार भी बाकी राज्यों के साथ ईस्टर्न कमांड ने यह एक्सरसाइज बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और अन्य सभी नार्थ ईस्ट के राज्यों में जारी की हुई है। …(व्यवधान) उससे पहले यू.पी., झारखंड, बिहार में भी यह एक्सरसाइज हुई है। …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You may complete your statement.

श्री मनोहर पर्रिकर: इस बारे में सेना ने इस वर्ष भी अलग-अलग राज्यों में कन्सर्न आफिशियल्स को …(व्यवधान) वेस्ट बंगाल में कन्सर्न आफिशियल्स को इसकी जानकारी दी थी। …(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : No.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप अपनी बात कम्प्लीट कीजिए। आप इसकी आदत डाल लीजिए।

… (व्यवधान)

श्री मनोहर पर्रिकर: इस एक्सरसाइज की ओरिजनल तारीख 28, 29 और 30 नवम्बर थी, जिसे पुलिस की एडवाइज के मुताबिक 1 और 2 दिसम्बर को बदला गया। …(व्यवधान) क्योंकि पुलिस ने कहा कि 28 तारीख को वहां बंद है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जायेगी, इसलिए 1 और 2 तारीख को यह एक्सरसाइज कर दी गयी। …(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : What is the purpose of the Army? Why are they being involved?… (*Interruptions*)

श्री मनोहर पर्रिकर : ट्रैफिक कन्जेशन के डर के कारण सब कार्यक्रम में ज्वाइंट इंसपैक्शन पुलिस के साथ की गयी है। …(व्यवधान) पुलिस के साथ कहां लगाना है, कैसे लगाना है, इसकी ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई है। मुझे इस सदन में कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सेना की इस प्रकार की रुटीन एक्सरसाइज को कंट्रोवर्सी बना लेना गलत है। …(व्यवधान) This is a political frustration rather than correct aspect being pointed out. यह केवल पोलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुदीप जी, डिसकशन मत कीजिए।

…(व्यवधान)

11.10 ½ hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न सं 241, श्री रमेश बिधूड़ी।

(Q. 241)

श्री रमेश बिधूड़ी : मैडम, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यह गरीबों को समर्पित सरकार है । ...(व्यवधान) पिछले दो सालों में गरीबों और पिछड़े लोगों के लिए कितनी एम्बुलेंस की व्यवस्था की गयी है और शव वाहनों के माध्यम से सरकारी अस्पतालों से उनके घर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है? ...(व्यवधान) इसके लिए जो वित्तीय सहायता दी गयी है, उनकी रखरखाव के लिए, ऐसे कितने केसेज पेंडिंग पड़े हैं? यही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

11.11 hours

(At this stage, Shri Deepender Singh Hooda and some other hon. Members Came and sat/ stood on the floor near the Table)

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: अध्यक्ष महोदया, जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से हमने राज्यों की जो रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पर हम राज्य सरकारों को सहायता देते हैं। ...(व्यवधान) वहां पर चाहे 108 की व्यवस्था हो, 102 की व्यवस्था हो या 104 की व्यवस्था हो, हम राज्य सरकारों की रिक्वायरमेंट के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से सहायता देते हैं। ...(व्यवधान) कुल मिलाकर यह राज्यों का विषय है, राज्य इसे देखते हैं।...(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी : मैडम, केन्द्र सरकार ने राज्यों को जो सहायता दी थी, राज्यों ने उससे क्या इम्पलीमेंटेशन की है?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिधूड़ी जी, एक मिनट रुकिए।

मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है, मैं आपको रोक नहीं रही हूं, ऐसा कई दिनों से चल रहा है। इन सारे लोगों का भी अधिकार है मंत्री से प्रश्न पूछना और उत्तर लेना। प्लीज, आप उन्हें बाधित न करें। आप इस तरफ रहें, इस तरह से इन लोगों को बाधित न करें। मंत्री के सामने कोई आकर नहीं खड़ा हो। मैं ऐसा निवेदन ही कर सकती हूं।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Do not do that. दूसरों के अधिकार को मत छीनो।

… (*Interruptions*)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): मैडम, कभी भी पिछले तीस-चालीस सालों में ट्रेज़री बेंच सामने आकर कोई खड़ा नहीं होता है, इसलिए इनको मना करना चाहिए, इसे एलाऊ नहीं करना चाहिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे नेमिंग करना पड़ेगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं एक बार वार्निंग दे रही हूं। I am warning you. अगर आप लोग इधर आएंगे तो I will have to name you.

…(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी : मैडम, मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार को इन्होंने जो हेल्प की है, राज्य सरकारों ने ऐसी कितनी एम्बुलेंसेज चलाई हैं, उनके आंकड़े चाहिए? …(व्यवधान) जो वित्तीय सहायता दी गयी है, क्या राज्य सरकारें उनको इम्पलीमेंट कर रही हैं या नहीं?…(व्यवधान)

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: अध्यक्ष महोदया, जैसा मैंने कहा है, यह राज्यों का विषय है, राज्य सरकार की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके आधार पर हम उनको सहायता राशि देते हैं और विशेषकर क्वालिटी पर हमारा नियंत्रण होता है, बाकी वहां की राज्य सरकार की व्यवस्था है कि वे किस आधार पर वहां के लोगों को सुविधाएं देने के लिए अपनी योजना बनाए। …(व्यवधान) उसके बारे में मैंने कहा है कि 108, 102 और 104, अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग व्यवस्था है। …(व्यवधान) उसके लिए उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए सहायता हम देते हैं और क्वालिटी में जो कंट्रोल हो सकता है, जो सपोर्ट हो सकता है, उसके लिए आर्थिक सहायता हम करते हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री जितेन्द्र चौधरी - उपस्थित नहीं।

SHRI BHEEMRAO B. PATIL : I would like to know whether the Government of India has provided any technical and financial support to medial ambulance services in the Telangana State under the National Health Mission (NHM)?… (*Interruptions*) How much fund has been spent on this? Please provide the details thereof… (*Interruptions*)

I would also like to know whether the Government of India has received a proposal for the financial assistance from the State of Telangana to strengthen the healthcare system in the Telangana State, especially for ambulance services… (*Interruptions*).

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: अध्यक्ष महोदया, जहां तक तेलंगाना राज्य का सवाल है, मैंने बताया है कि राज्य सरकारें जो डिमाण्ड करती हैं, उसके आधार पर चाहे 108 का हो, 102 हो या 104 हो, राज्य सरकारों के जो प्रस्ताव आते हैं, उसके आधार पर हम अनुदान देने का काम करते हैं। …(व्यवधान) निर्णय राज्य सरकारों को करना पड़ता है। …(व्यवधान) जहां तक क्वालिटी का सवाल है, हम उनको टेक्नीकल सपोर्ट करते हैं और हमारी जो गाइडलाइन है, उसके आधार पर हम सपोर्ट करते हैं।

श्री दद्दन मिश्रा : माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दिनों देश के विभिन्न भागों में घटित कुछ हृदय विदारक घटनाओं की ओर मीडिया ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया था।…(व्यवधान) देश के विभिन्न अस्पतालों में मृत शरीरों को कंधे पर ढ़ोते हुए पूरे देश ने अपनी आंखों से देखा है। …(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह सवाल है कि अस्पतालों में जो मृत्यु हो जाती है, उसके उपरांत क्या मृत शरीरों को उनके घरों को आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के अन्तर्गत पहुंचाने का प्रावधान है?..(व्यवधान)

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, मैं उसके संबंध में बताना चाहूंगा कि जहां तक जो स्पेशल व्यवस्था करने का सवाल है, राज्य सरकार उस विषय को देखती है। …(व्यवधान) हमारा काम केवल उस विषय को सपोर्ट करना है और अगर इस प्रकार की कोई घटना घटी है तो यदि माननीय सदस्य उस बारे में जानकारी देंगे तो उस पर हम जरूर पूछताछ करेंगे और उसका जवाब माननीय सदस्य को देंगे।…(व्यवधान)

श्री अजय मिश्रा टेनी : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि प्रश्न के उत्तर में बताया गया है, आपातकालीन मेडिकल एम्बुलेंस सेवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के द्वारा उनके प्रस्तावों पर आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था, वित्तीय फंडिंग और टैक्नीकल सुविधा दी जाती है।…(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से उत्तर प्रदेश के विषय में जानना चाहता हूं। जैसा कि उत्तर में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी एम्बुलेंस 108 डायल के तहत 988, 102 और 104 डायल कर सकते हैं।…(व्यवधान) कुल 3258 एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश में एन.आर.एच.एम. के तहत उपलब्ध कराई गई हैं जिस पर केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को 251 करोड़ रुपए से अधिक रुपया 2015-2016 में उपलब्ध कराया गया है।…(व्यवधान) मेरा प्रश्न यह है कि आपातकालीन

मेडिकल एम्बुलेंस के तहत जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, एन.आर.एच.एम. के तहत चलाई जाने वाली एम्बुलेंस में यू.पी.सरकार ने राजनैतिक कारणों से उक्त एम्बुलेंस का नाम समाजवादी एम्बुलेंस सेवा रखा है। …(व्यवधान) मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों पर किया गया है या उन्होंने केवल राजनैतिक लाभों के लिए उन एम्बुलेंस सेवाओं को जो एन.आर.एच.एम. के तहत उपलब्ध कराई जाती हैं, समाजवादी एम्बुलेंस सेवा का नाम दिया है?…(व्यवधान)

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा है, जहां तक एम्बुलेंस की संख्या और सेवा का सवाल है, आप देखेंगे कि अभी तक कुल 3258 एम्बुलेंस उपलब्ध करायी गयी हैं। …(व्यवधान) जहां तक उनकी राजनैतिक व्यवस्था का सवाल है, अगर इस प्रकार का कोई विषय रिकार्ड में आता है तो उसके बारे में सरकार जरूर विचार करेगी।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या - 242।

श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे - उपस्थित नहीं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी।

(Q. 242)

माननीय अध्यक्ष : श्री पशुपति नाथ सिंह - अनुपस्थित।

श्री गणेश सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, जन धन योजना में लगभग 25.5 करोड़ खाते जो खोले गये हैं, यह प्रधान मंत्री जी द्वारा ऐतिहासिक कार्य किया गया है। ...(व्यवधान) अब तक जो नोटबदली हुई, जिसमें कैशलैस सोसायटी बनाने का जो अभियान शुरु हुआ है, ऐसी स्थिति में जन धन के खातों का महत्व बढ़ गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के खाते फिर से एक्टीवेट नहीं हुए हैं, उनको क्या एक्टीवेट करने के कोई उपाय किये जा रहे हैं?...(व्यवधान) क्या प्रधान मंत्री जी द्वारा जो गरीब कल्याण योजना शुरु की जाने वाली है, क्या उसमें इन सभी खातों को जोड़ा जाएगा तथा जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा लगभग जो अभी तक 24 लाख लोगों को मिली है, क्या उसे और प्रभावी बनाने के लिए कोई उपाय किये जाएंगे?...(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य जी को अवगत कराना चाहूंगा कि 28 अगस्त 2014 को माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा जन धन योजना द्वारा जो अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी योजना की घोषणा की गई थी,...(व्यवधान) वह बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। जैसा बताया गया है कि इस योजना के अन्तर्गत खोले गये कुल खाते 25.66 करोड़ हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये खातों की संख्या 15.73 करोड़ है, शहरी क्षेत्रों में 9.94 करोड़ खाते खोले गये हैं। ...(व्यवधान) इस स्कीम के तहत खोले गये खातों में 72,834 करोड़ रुपए जमा हुये हैं। ...(व्यवधान) ये सारे खाते अपने-आप में कार्यरत हैं और चलाये जा रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह अपने-आप में एक विशेष लाभ है और इसके माध्यम से जितनी अधिकतम सहायता की जा सकती है, वह सहायता दी जायेगी। ...(व्यवधान) उन खातों में सामान्य लेन-देन होने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष जी, जन-धन खाता खोलने का जो निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, वह वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। ...(व्यवधान) यह देखने में आया है कि देश में गरीब वर्ग के जो लोग हैं, ...(व्यवधान) जो गांवों में रहते हैं, ...(व्यवधान) उनको इस विषय में जैसे कि 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' और 'अटल पेंशन योजना' शुरू की गईं, ...(व्यवधान) जिनसे उनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके,...(व्यवधान) लेकिन उनमें जागरूकता का अभाव होने के कारण और लोगों को मालूम न होने के कारण, जैसे कि ओवर ड्राफ्ट की सुविधा है, ...(व्यवधान) अगर वे उन्हें 45 दिनों तक या लगातार कुछ दिनों तक संचालित नहीं करते हैं तो उनको ओवर ड्राफ्ट की सुविधा नहीं मिलती है। ...(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन गरीबों और वंचितों के बीच में, शाखा के लोग वहां पर शिविर लगा कर, क्या उन्हें जागरूक करने के लिए कोई विशेष अभियान चलायेंगे? …(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी के सुझाव से सहमत हूं, इसमें जो भी अधिकतम प्रयास हो सकता है, …(व्यवधान) क्योंकि इस काम में सभी बैंक्स सहयोग कर रही हैं। …(व्यवधान) बैंकों के एक सहयोगी, बिजनेस फैसिलिटेटर, वह भी इस काम में मदद कर रहा है। …(व्यवधान) जहां-कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकता होगी, उसका उपयोग किया जायेगा। …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Again I am requesting all of you on this side to please go to the other side. Do not disturb other Members.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह अच्छा नहीं है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप दूसरों को डिस्टर्व नहीं करें।

…(व्यवधान)

(Q. 243)

श्री कीर्ति आज़ाद : अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं आपकी ओर से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को आज उनके जन्म दिन पर हार्दिक बधाई देता हूं। ...(व्यवधान) साथ ही साथ, मैं उनको इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रश्न का बहुत ही विस्तृत रूप से जवाब दिया है। ...(व्यवधान) हम सभी जानते हैं कि पिछड़े राज्यों में, विशेषकर बिहार है या उसके आस-पास के पूर्वोत्तर राज्य हैं, ...(व्यवधान) वहां स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमराई हुई है। ...(व्यवधान) हमने कुछ दिन पहले भी देखा और पहले प्रश्न में भी कहा गया कि शव वाहन तक नहीं मिल पाते हैं, ...(व्यवधान) लेकिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो यह शुरुआत की है कि ऑनलाइन प्रिसक्रिप्शंस और ऑनलाइन डॉक्टरों से मिलना, विशेाकर बिहार जैसे राज्य में जहां सरकारी डॉक्टर्स भी प्राइवेट नौकरी करते हैं। ...(व्यवधान) ऐसी परिस्थिति में और खासकर जब स्वास्थ्य राज्य का विाय है, ...(व्यवधान) कई योजनायें स्वास्थ्य मंत्रालय एवं दूसरे मंत्रालय की तरफ से शुरू की गयी हैं, लेकिन वे पूरे तरीके से वहां नहीं आ पाती हैं। ...(व्यवधान) ऐसी परिस्थिति में आई.टी. सॉल्यूशंस के माध्यम से किस प्रकार से राज्य और केन्द्र सरकार में समन्वय बनेगा, ...(व्यवधान) जिससे सारी चीजें ऑनलाइन हो सकेंगी। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, समन्वय करना ही तो सबसे कठिन कार्य है। इन्होंने जवाब के पार्ट बी-1 में कहा है :

"Health record is being undertaken in a phased manner."

जब यह शुरू ही नहीं हुआ है तो फेज्ड मैनर में कब होगा? मैं यह जानना चाहता हूं कि यह शुरू कब होगा और यह फेज्ड मैनर खत्म कब होगा? जब सरकार चिकित्सा को आईटी सोल्यूशन्स के माध्यम से डायरेक्टली ऑनलाइन करना चाहती है, सरकार की ओर से क्या इसकी कोई टाइमलाइन बनाई गयी है? माननीय मंत्री जी मुझे यह बताएं कि इसे फेज्ड मैनर में कैसे पूरा करेंगे, जब यह काम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है?

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: अध्यक्ष महोदया, हमने इसे अगस्त, 2016 में शुरू किया है और इसे निरन्तर आगे बढ़ाने के लिए हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। अभी-अभी हमने इसे एनाउंस किया है।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY : Madam, it is a very important Question. We are all concerned about it. … (*Interruptions*) The system that is going on presently is not helping the common people sometimes. So, if information technology solutions are used properly, they will help each and every one in the country. Sometimes, it is seen that the writings of the doctors are not read properly.… (*Interruptions*) If those papers are linked with information

technology and supplied to the patients, it will help the common man because in today's world, we have got a lot of different critical diseases including AIDS, cancer and other diseases concerning children. … (*Interruptions*) A lot of research has been done and medical facilities are being given to people. … (*Interruptions*) If they are brought under information technology, it will surely help the country.… (*Interruptions*)

I would like to ask the hon. Minister as to whether these medical facilities provided with IT solutions would be available all over the country including UTs and each and every village in the rural areas? Have these facilities reached those areas or not? … (*Interruptions*)

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: अध्यक्ष महोदया, जैसा माननीय सदस्या ने कहा है और मुझे मालूम है कि पूर्वी क्षेत्रों और दूरदराज के इलाकों को कैसे प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक सक्षम बनाया जाए। जैसा मैंने पहले कहा है, हमने इस स्कीम को अगस्त, 2016 में शुरू किया है। हमारी यह कोशिश है कि राज्य सरकारों के जितने सेंटर्स हैं, पी.एच.सी. हैं और केन्द्र सरकार है, इन सभी का समन्वय होगा। एक बार इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी केन्द्र के अंदर अगर पेशेंट जाता है तो उसका सारा रिकॉर्ड कम्पयूटराइज्ड होगा। इसके पीछे एक मंशा यह है, जिससे पेशेंट को भटकना न पड़े और निश्चित रूप से हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं।...(व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया : माननीय अध्यक्ष महोदया, जो वर्तमान में डिमॉनेटाइजेशन हुआ, जिसमें यह पता चला है कि जन धन एकाउण्ट्स में बड़े परिमाण में बेनामी ट्रांजैक्शन हुई है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY : Madam, information technology in health care can reduce the cost of health care and increase the quality of health care. … (*Interruptions*) The Government has undertaken a very good project to implement but before implementing information technology solutions, we have to standardise information. Has the Government taken steps to standardise information in health care? … (*Interruptions*) For example, India is the only developed country without National Drug Codes. Without National Drug Codes,

we cannot implement it. We use disease codes of WHO which are not localised. We also do not have laboratory codes. So, before implementing information technology, we have to standardise information. … (*Interruptions*) Is the Government planning to standardise information in health care using National Drug Codes? … (*Interruptions*)

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: अध्यक्ष महोदया, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, इसके बारे में निश्चित रूप से हमारा यही प्रयास है और हम इसके बारे में विचार करेंगे और भविष्य में बहुत जल्दी इस बारे में अपना कार्यक्रम लेकर आएंगे। निश्चित रूप से हम इसे भी कवर करेंगे। हमारे पास लगभग साढ़े पांच सौ ऐसे केन्द्र हैं जहां पर प्रयोग के तौर पर इसे कम्पयूटराइज किया हुआ है।

श्री शरद त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप राष्ट्रीय टेलिमेडिसन नेटवर्क योजना के अंतर्गत देश के बहुत सारे पी.एच.सी. और सी.एच.सी. केन्द्रों को जोड़ने की व्यवस्था बना रहे हैं। चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राजस्थान और त्रिपुरा को भी आपने वित्तीय सहायता प्रदान की है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जहां सबसे अधिक आबादी है और वहां सबसे अधिक सी.एच.सी. और पी.एच.सी. हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के सी.एच.सी. और पी.एच.सी. केन्द्रों को जोड़ने की व्यवस्था कब तक करेंगे?

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : महोदया, माननीय सदस्य ने विशेषकर उत्तर प्रदेश के सी.एच.सी., पी.एच.सी. और डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स के बारे में कहा है। मैं उन्हें बताना चाहता हं कि चूंकि यह राज्य सरकार का विषय होता है, इसलिए इसे राज्य सरकार को देखना पड़ता है। परंतु उनको तकनीकी सलाह देना और फाइनेंशियली सपोर्ट करना हमारा विषय है। जिन-जिन केन्द्रों के लिए हमारी यह योजना है, इस योजना को ऑनलाइन करना, रजिस्ट्रेशन करना आदि ये सब हमने केवल पेशेन्ट्स की सुविधा की दृष्टि से किया है और यह निश्चित है कि अगर इस प्रकार के प्रस्ताव वहां से आयेंगे तो उन्हें ऑनलाइन किया जायेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या - 244 ।

श्री केसिनेनी श्रीनिवास - उपस्थित नहीं।

श्री असादुद्दीन ओवैसी - उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी।

(Q. 244)

श्री गोपाल शेट्टी : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस प्रश्न पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं रक्षा मंत्री, श्री मनोहर पर्रिकर जी को मुम्बई शहर के सभी नागरिकों की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा तथा आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने हमें मुम्बई शहर के उस प्रश्न को सदन में उठाने का मौका दिया। श्री पर्रिकर जी ने सिर्फ मुम्बई ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों की समस्याओं का समाधान किया, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा।

महोदया, मैं डायरेक्ट इस विषय पर आना चाहता हूं। मैं रक्षा मंत्री जी को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वह रक्षा मंत्रालय का पदभार संभालने के बाद मंत्रालय में बहुत सारे सुधार लाये हैं। मैं खास तौर से बताना चाहता हूं कि वह कामों में कितनी पारदर्शिता लाये हैं। पहले सौ करोड़ के सौदों में जो डिबेट, डिस्कशन होता था, उसे उन्होंने बीस करोड़ पर लाने का काम किया है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी पारदर्शिता और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनो में रक्षा सौदों में पारदर्शिता लाने के लिए और 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को बल देने के लिए हम विदेशों से जो भी रक्षा उपकरण और औजार आदि खरीदते हैं, उसमें बिचौलिये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। इसलिए हमारे देश में 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को ज्यादा बल देने तथा बढ़ावा देने के लिए आने वाले दिनों में रक्षा मंत्रालय क्या-क्या काम करने जा रहा है, उस पर मैं रक्षा मंत्री जी से मार्गदर्शन चाहूंगा?

श्री मनोहर पर्रिकर : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बिचौलियों से संबंधित जितने भी इश्यूज सामने आ रहे हैं, वे पुरानी सरकार के समय में बिचौलियों ने जो कमीशन लिया था, उनके बारे में आ रहे हैं। हमने अभी बहुत अच्छी ब्लैक लिस्टिंग पालिसी और एजेन्ट्स के बारे में एक पालिसी डिक्लेयर की है। हमने जो नया डी.पी.पी. किया है, उसमें इंडियन डिजाइन डैवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या - 245 ।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण - उपस्थित नहीं।

श्री छेदी पासवान - उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी।

(Q. 245)

श्री बलभद्र माझी : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर रखा है, उससे हमें यह विवरण प्राप्त हो रहा है कि दिनों-दिन कैंसर पेशेन्ट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। विशेषकर यदि आप ओडिशा को देखें तो वर्तमान में वहां से सबसे ज्यादा कैंसर पेशेन्ट टाटा मैमोरियल हास्पिटल, मुम्बई जाते हैं। वहां जाने के लिए एक कोणार्क एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसमें इनकी बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। सरकार के द्वारा जितने भी इंस्टीट्यूट्स ओडिशा में खोले गये हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वह ओडिशा में कुछ और कैंसर इंस्टीट्यूट्स खोलने की कृपा करे तथा वहां जो कालेजिज हैं, यदि उनमें ट्रीटमैन्ट की व्यवस्था की जाए तो काफी लाभदायक होगा। धन्यवाद।

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने विशेषकर ओडिशा के बारे में चिंता जाहिर की है। ...(व्यवधान) उन्होंने एक बात कही है कि इसकी संख्या में जो बढ़ोत्तरी हुई है, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि इस समय कैंसर से जो लोग प्रभावित हैं, उसका कारण यह है कि कई प्रकार के तंबाकू उत्पादों का उपयोग करना है। ...(व्यवधान) जिसके कारण इसका थोड़ा प्रभाव बढ़ा है। ...(व्यवधान) जहां तक ओडिशा का जो सवाल है, निश्चित ही इसके बारे में जो संख्या है, उसके बारे में अगर कोई प्रस्ताव सरकार का आएगा तो उस पर जरूर ही विचार किया जाएगा। ...(व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल : अध्यक्ष महोदया, बिहार की जनसंख्या 11 करोड़ है। उसके बावजूद भी वहां पर कैंसर के इलाज के लिए कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं है। ...(व्यवधान) मरीजों को इलाज करवाने के लिए दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता है। ...(व्यवधान) कहने को तो इन्होंने लिस्ट में दो-दो टर्शरी सैंटर्स और एक स्टेट कैंसर सैंटर दिया है। ...(व्यवधान) लेकिन कहीं पर भी न तो gamma knife की सुविधा उपलब्ध है, न ही linear accelerator की सुविधा उपलब्ध है और इतना ही नहीं जो बेसिक chemotherapy होनी चाहिए, जो बेसिक radiation therapy होनी चाहिए, वह सुविधा भी वहां उपलब्ध नहीं है। ...(व्यवधान) आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरा यह प्रश्न है कि बिहार की 11 करोड़ जनता को टर्शरी केयर सैंटर कब उपलब्ध होगा, जिससे कि सभी तरह के कैंसर का इलाज बिहार में ही हो सके और मरीजों को दिल्ली नहीं जाना पड़े। ...(व्यवधान)

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा विषय कहा है कि हमने अभी तक वहां पर दो टर्शरी केंद्र संचालित किए हैं। ...(व्यवधान) जहां तक प्रस्ताव का सवाल है, अगर राज्य

सरकार इस प्रकार का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजती है तो केंद्र सरकार की ओर से उनको मदद अवश्य की जाएगी और विशेष योजना के तहत किया जाएगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 246 - श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव - उपस्थित नहीं।

श्री विनायक भाऊराव राऊत।

(Q. 246)

माननीय अध्यक्ष : विनायक राऊत जी, अपना प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं हाऊस एडजर्न नहीं कर रही हूँ, आप आराम से अपना प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह आपका अधिकार है, प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री विनायक भाऊराव राऊत : अध्यक्ष महोदया, भारत और इज़रायल दोनों ही सशक्त देश हैं। ...(व्यवधान) दोनों की स्थिति अगर देखें तो एक जैसी ही है। ...(व्यवधान) इज़रायल एक यहूदी देश है और भारत हिंदू देश है। ...(व्यवधान) इन दोनों देशों को तोड़ने के लिए कई देशों ने प्रयास किए हैं। ...(व्यवधान) लेकिन मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इस सरकार ने और माननीय प्रधान मंत्री जी ने इज़राइल को भेंट देने के बाद इन दोनों के संबंधों में कई अच्छे सुधार आए हैं। ...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी की विज़िट होने के बाद से इज़रायल और भारत के बीच कौन-कौन से मुद्दों पर समझौता हुआ है, उसकी आगे क्या प्रगति हुई है?...(व्यवधान)

श्री मनोहर पर्रिकर : अध्यक्ष महोदया, सवाल के जवाब में हमने कहा है कि जो-जो मुद्दे डिस्कस हुए हैं, वे सीक्रेट एग्रीमेंट्स हैं। ...(व्यवधान) उसके तहत हम लोग उसकी डिटेल्स नहीं दे सकते हैं। ...(व्यवधान) लेकिन मैं माननीय सदस्य को इतना आश्वस्त करूंगा कि हमारे कई प्रकल्प अच्छे चल रहे हैं। ...(व्यवधान) उसके अंदर कई टैक्नोलॉजीस के बारे में हम लोग ज्वाइंट डेवल्पमेंट कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री विनायक भाऊराव राऊत : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी उत्तर तो दे चुके हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि इज़रायल ने जैसे टैक्नोलॉजी में भी अच्छी प्रगति की है, उसका फायदा भी भारत देश को हो सकता है, उसके बारे में भी आप उनके साथ कैसा व्यवहार करने वाले हैं? ...(व्यवधान) उनके साथ कौन से मुद्दों पर समझौता करने वाले हैं? ...(व्यवधान)

श्री मनोहर पर्रिकर : अध्यक्ष महोदया, कई टैक्नोलॉजीस में इज़रायल ने काफी अच्छी प्रगति की है। ...(व्यवधान) ऐसे कई अन्य प्रकल्प हैं, जिनके बारे में मैं ज्यादा जानकारी यहाँ नहीं दे सकता हूँ।...(व्यवधान) इसके ऊपर हम लोगों ने उनके साथ समझौते भी किए हैं। ऐसे कई अन्य प्रकल्प हैं, जिनके बारे में मैं ज्यादा जानकारी यहाँ नहीं दे सकता हूँ।...(व्यवधान) उसमें एक प्रकल्प (LR SAM) Long Range Surface to Air Missile है, जिससे आने वाली मिसाइल इंटरसेप्ट करने की क्षमता को हमारा

देश एक्वायर कर सकता है। ...(व्यवधान) अभी वह प्रकल्प फाइनल स्टेज पर पहुंचा है। ...(व्यवधान) ऐसे कई अन्य प्रकल्प हैं, जिनके बारे में ज्यादा जानकारी मैं यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ।...(व्यवधान)

डॉ. मनोज राजोरिया : महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।...(व्यवधान) जैसा कि पूरे देश को मालूम है कि आज हमारा पड़ोसी पाकिस्तान विभिन्न तरीकों से अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके आतंकवादियों को सेना के भेष में और पुलिस के भेष में भेजकर हमारे देश के सैनिकों और आम आदमियों पर हमला कर रहा है।...(व्यवधान) इसी का परिणाम रहा कि तीन दिन पहले जम्मू-कश्मीर में जो हमला हुआ, उसमें मेरे संसदीय क्षेत्र धौलपुर के एक वीर श्री राघवेन्द्र सिंह परिहार शहीद हो गए।...(व्यवधान) जिस प्रकार से कल धौलपुर में हजारों की संख्या में युवा और आम जनों ने उस शहीद को श्रद्धाँजलि दी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रद्धांजलि दी।...(व्यवधान) लेकिन जो जनता का जोश था, युवाओं का जोश था, उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और भारत माता की जय के नारे लगाए।...(व्यवधान) जो जुनून देश की जनता और युवाओं का देश के साथ है, मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो औछी हरकतें हैं, पाकिस्तान की ऐसी हरकतों को रोकने के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को फुलप्रूफ बनाने के लिए और देश के अन्दर आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए वे क्या उपाय कर रहे हैं?...(व्यवधान) वे इजराइल की क्या मदद ले रहे हैं।...(व्यवधान) इजराइल बहुत से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है।...(व्यवधान) हम भी ऐसी ही परिस्थितियों में हैं।...(व्यवधान) मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इजराइल का कौन सा सहयोग है, जिससे हम अपनी सीमाओं को सेफ कर सकें, उनकी सुरक्षा कर सकें। धन्यवाद।...(व्यवधान)

श्री मनोहर पर्रिकर : हमें बहुत दुःख है कि हमारे वीर जवान तीन दिन पहले शहीद हो गये।...(व्यवधान) लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में हम लोगों ने कई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।...(व्यवधान) जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फेन्शिंग, लेजर फेन्शिंग जैसे कई उपाय हैं।...(व्यवधान) उनके डिटेल्स अगर मैं बता दूँ तो हमारे दुश्मन को उनकी जानकारी हो जायेगी।...(व्यवधान) लेकिन हमने उनका इस्तेमाल करना शुरू किया है और हम इसमें इजराइली कम्पनियों की भी मदद ले रहे हैं।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Q. No. 247, Shri Krupal Balaji Tumane – Not present. Now the Minister.

(Q. 247)

SHRI RABINDRA KUMAR JENA : Thank you, Madam Speaker, for giving me an opportunity to ask a supplementary with regard to the Ministry of Finance on the issue of loan to MSMEs.… (*Interruptions*)

Madam, there are clear-cut guidelines issued by the Ministry of Finance, Government of India and the Reserve Bank of India to provide loan to the priority sector including small and medium industries. … (*Interruptions*) But what we see on the ground is that there is a blatant violation of these guidelines during the review of banker's performance, all over the country including my district of Odisha. … (*Interruptions*)

So, my specific question to the hon. Minister is that whether the Government would consider canceling the licenses of those branches or closing down those branches, which continue to violate the norms of the Government of India and the RBI, and do not lend to the small and medium industries. … (*Interruptions*)

श्री संतोष कुमार गंगवार : एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में लोन देने के लिए सरकार बहुत सक्रियता के साथ प्रयत्नशील है।…(व्यवधान) माननीय सदस्य जो शिकायत दे रहे हैं, अगर उसकी जानकारी आयेगी तो उसमें प्रभावी कार्रवाई की जायेगी।…(व्यवधान) मैं यहाँ यह बताना चाहूँगा कि प्रधान मंत्री जी की योजना के तहत 5 से 10 लाख रूपये तक के जो ऋण दिये जा रहे हैं, वे बहुत ही आसान शर्तों के हिसाब से दिये जा रहे हैं।…(व्यवधान) अगर कोई आवेदन करेगा तो उसमें सहयोग किया जायेगा।…(व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सोनकर : महोदया, आपने मुझे प्रश्न अनुपूरक पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।…(व्यवधान)

महोदया, भारत सरकार का एक स्पष्ट निर्णय है कि अनुसूचित समाज के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, उनके उद्योग बढ़ें, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि चार परसेंट तक सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज और गवर्नमेंट के जो सारे विभाग हैं, उनके लिए चार परसेंट तक प्रिक्योरमेंट अनुसूचित समाज के इन्टरप्राइजेज से खरीदने के लिए निर्णय किया गया है।…(व्यवधान) ऐसा निर्णय भारत सरकार का किया गया है।…(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार का जो निर्णय है, जिसके माध्यम से 4 परसेंट तक एससी एंटरप्राइसेज़ से वह प्रोक्योरमैंट करना है, सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय इसके लिए क्या योजना बना रहा है, जिससे वह चार परसेंट का टार्गैट पूरा हो? …(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार : यह विषय हमारे मंत्रालय से संबंधित नहीं है, परंतु मैं एम.एस.एम.ई. को आपके सुझाव से अवगत कराने का काम करूँगा। …(व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि पूर्वांचल के राज्यों, खासकर मणिपुर में जनधन योजना के बाद प्रधान मंत्री की जो ऋण योजना है, पर्वतीय क्षेत्रों में सिंगल मैनेजर ब्रांच होने के कारण वहाँ इस प्रकार के लोन में भारी तकलीफें आ रही हैं। …(व्यवधान) जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है, वहाँ पर तो यह ऋण मिलना उपलब्ध है, लेकिन दूसरी जगह पर यह ऋण उपलब्ध नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ऐसे राज्यों में जहाँ इनसर्जैन्सी है, जहाँ सिंगल मैनेजर ब्रांचेज़ हैं, खासकर मणिपुर में, वहाँ पर क्या इन ऋणों के बारे में समीक्षा करेंगे? …(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार : माननीय अध्यक्ष महोदया, अगर वहाँ पर ऐसी कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जाएगा और हम पूर्वांचल क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिखवा रहे हैं। …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री आर के.सिंह, क्या आप इस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री आर.के.सिंह : जी हाँ। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद। मैं इंडस्ट्रियल एरिया डैवलपमैंट अथॉरिटी का Managing Director भी रहा हूँ और मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरिएंस के आधार पर कि अगर लघु और मध्यम उद्योग नहीं बढ़े हैं तो उसका एक मुख्य कारण बैंक हैं। …(व्यवधान) स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ को और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को लोन देने में बैंक बहुत कोताही करते हैं। या तो लोन देने से मना कर देते हैं या देते भी हैं तो जितना आवश्यक है, उससे कम देते हैं। इससे जब इंडस्ट्री शुरू होती है तो वह प्रारंभ से ही बीमार रहती है। वित्त मंत्री महोदय भी यहाँ हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रगति हो और स्माल इंडस्ट्रीज़ पनपें, तो बैंकों को अकाउंटेबल बनाएँ। यहाँ पर मैं स्पेशली बिहार के बारे में बता सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में भी यही हालत है। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बैंक से लोन मिलना दूभर है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप पूछिए कि क्या अकाउंटेबल बनाएँगे?

श्री आर.के.सिंह : मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या वे बैंकों को अकाउंटेबल बनाएँगे, इसका रिव्यू करेंगे?

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ और प्रधान मंत्री जी की विशेष रुचि इस ओर है। मुद्रा योजना जो 1 करोड़ रुपये तक जाती है, उसमें इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसमें जो भी संभव सहयोग होगा, वह किया जाएगा। …(व्यवधान)

श्री लक्ष्मी नारायण यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या एमएसएमई में जो डेयरी सैक्टर है, उसको भी जोड़कर लोगों को, भले ही मुद्रा योजना में उसको जोड़ें, पर क्या उसके लिए ऋण देने के लिए उन बैंकों को बाध्य करेंगे, क्योंकि वर्तमान में देखा जा रहा है कि बैंक डेयरी उद्योग के लिए कोई भी ऋण नहीं देते हैं जिससे गाँवों में बहुत से रोज़गार क्रियेट हो सकते हैं। …(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार : मुद्रा योजना में ऋण दिये जा रहे हैं और उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो उस पर हम ध्यान देंगे कि उसमें और क्या सहयोग हो सकता है। मुद्रा योजना में डेयरी उद्योग शामिल है, यह बात मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : लेकिन यह बात तो साधारणतः आ गई कि थोड़ी कठिनाई एमएसएमई को तो आती है। मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें।

श्री संतोष कुमार गंगवार : इस पर ध्यान दिया जाएगा और सहयोग किया जाएगा। …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Thank you.

Hon. Members, please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 noon.

11.49 hours

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.01 hours

The Lok Sabha re-assembled at One Minute past
Twelve of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Sarvashri Mallikarjun Kharge, Jyotiraditya M. Scindia, K.C. Venugopal, Jitendra Chaudhary, Jai Prakash Narayan Yadav, Dr. P. Venugopal, Prof. Saugata Roy, Sarvashri Kodikunnil Suresh, N.K. Premachandran, Rajesh Ranjan, P. Karunakaran, Md. Badaruddoza Khan, Smt. P.K. Sreemathi Teacher, Sarvashri Sudip Bandyopadhyay and P.K. Biju on different issues.

The matters though important do not warrant interruption of business of the day. The matters can be raised through other opportunities. I have, therefore disallowed all the notices of Adjournment Motion.

… (*Interruptions*)

12.02 hours

(*At this stage, Shri K.C. Venugopal, Shrimati Arpita Ghosh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

… (*Interruptions*)

12.02 ½ hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, the House will take up Papers to be Laid on the Table.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MANOHAR PARRIKAR): I beg to lay on the Table –

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Aeronautical Development Agency, Bangalore, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Aeronautical Development Agency, Bangalore, for the year 2015-2016.

[Placed in Library. See No. LT 5585/16/16]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Defence Institute of Advanced Technology, Pune, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Defence Institute of Advanced Technology, Pune, for the year 2015-2016.

[Placed in Library. See No. LT 5586/16/16]

… (*Interruptions*)

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज) : महोदया, मैं श्रीमती मेनका संजय गांधी जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं : -

(1) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 5587/16/16]

…(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : -

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library. See No. LT 5588/16/16]

(ख) (एक) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library. See No. LT 5589/16/16]

(ग) (एक) 31.6.2016 को समाप्त हुए तिमाही के लिए भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक परिसमापन), कोलकाता के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) 31.6.2016 को समाप्त हुए तिमाही के लिए भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक परिसमापन), कोलकाता के बारे में परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library. See No. LT 5590/16/16]

(दो) (एक) स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[Placed in Library. See No. LT 5591/16/16]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : -

(क) (एक) न्यू दिल्ली टयूबरकुलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) न्यू दिल्ली टयूबरकुलोसिस सेंटर,नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library. See No. LT 5592/16/16]

(2) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ओषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 2016 जो 29 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 640(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ओषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 18 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 532(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ओषधि और प्रसाधन सामग्री (सातवां संशोधन) नियम, 2016 जो 4 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1041(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library. See No. LT 5593/16/16]

(3) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य सुरक्षा और नामक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योगज) पांचवां संशोधन विनियम, 2016 जो 15 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अध्सूचना संख्या एफ.सं. 1-12/मानक/एसपी (मिठाई, मिख़्ठान)/ एफएसएसएआई-2015 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) चौथा संशोधन विनियम, 2016, जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 1-120(2)/मानक/विकिरण चिकित्सा/एफएसएसएआई-2015 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद और खाद्य योगज) छठा संशोधन विनियम, 2016, जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 1-120 (1) / मानक / विकिरण चिकित्सा/ एफएसएसएआई-2015 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विष और अवशिष्ट) चौथा संशोधन विनियम, 2016, जो 13 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 1-99/एसपी(संदूषक)/रेग/एफएसएसएआई-2015 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) तीसरा संशोधन विनियम, 2016, जो 15 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफोसौ 3-14पी/अधिसूचना (न्यूट्रास्यूटिकल्स/एफएसएसएआई-2013 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद और खाद्य योगज) चौथा संशोधन विनियम, 2016, जो 15 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 3-14एफ/अधिसूचना (न्यूट्रास्यूटिकल्स)/ एफएसएसएआई-2013 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद और खाद्य योगज) सातवां संशोधन विनियम, 2016, जो 27 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. मानक/एसपी (वाटर एंड बेवरेजेज)/अधिसूचना (2)/ एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद और खाद्य योगज) आठवां संशोधन विनियम, 2016, जो 14 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधूचना संख्या एफ.सं. मानक/सीपीएलक्यूोसीपी/ ईएम/ एफएसएसएआई-2015 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञप्तिकरण और रजिस्ट्रीकरण) पहला संशोधन विनियम, 2016, जो 15 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 2-15015/30/2012 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्रियों पर प्रतिषेध और निर्बन्धन) दूसरा संशोधन विनियम, 2016, जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सौमानक/एफ एंड वीपी/अधिसूचना (02)/ एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library. See No. LT 5594/16/16]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : -

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016, जो 22 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 716(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण नियम, 2016, जो 22 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 717(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (लेखे) नियम, 2016, जो 27 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 742(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (निगमन) तीसरा संशोधन नियम, 2016, जो 27 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 743(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (शेयर पूंजी और ऋण-पत्र) चौथा संशोधन नियम, 2016, जो 12 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 791(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कंपनी (मध्यस्थता और सुलह) नियम, 2016, जो 9 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 877(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2016, जो 23 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 908(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कंपनी (निगमन) चौथा संशोधन नियम, 2016, जो 1 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 936(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) दूसरा संशोधन नियम, 2016, जो 7 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1049(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) से (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 5595/16/16]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं.का.आ. 2922(अ), जो 12 सितंबर 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची पांच में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 5596/16/16]

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखती हूं : -

(1) (एक) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त(1)में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 5597/16/16]

(3) किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 की उपधारा (3) के अंतर्गत किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016, जो 21 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 898 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 5598/16/16]

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013 –

(1) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Dynamics Limited, Hyderabad, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Bharat Dynamics Limited, Hyderabad, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library. See No. LT 5599/16/16]

(2) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Electronic Limited, Bengaluru, for the year 2015-2016.

[Placed in Library. See No. LT 5600/16/16]

(ii) Annual Report of the Bharat Electronic Limited, Bengaluru, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(3) (i) Review by the Government of the working of the BEL Optronic Devices Limited, Pune, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the BEL Optronic Devices Limited, Pune, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library. See No. LT 5601/16/16]

(4) (i) Review by the Government of the working of the BEL-Thales Systems, Bengaluru, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the BEL-Thales Systems, Bengaluru, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library. See No. LT 5602/16/16]

12.03 hours

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE
6th to 8th Reports

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदया, मैं रेल अभिसमय समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं : -

(1) 'वर्ष 2016-17 के लिए रेल द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर और अन्य अनुषांगी मामले' के बारे में छठां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(2) 'भारतीय रेल के अवसंरचना निर्माण में इस्कॉन की भूमिका के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई' संबंधी सातवां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(3) 'अधिशेष रेल भूमि का वाणिज्यिक उपयोग रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) की भूमिका के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई' संबंधी आठवां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

...(व्यवधान)

12.04 hours

STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL
24th Report

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : महोदया, मैं कोयला मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2016-17)' के बारे में समिति (16वीं लोक सभा) के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 24वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

…(व्यवधान)

12.04 ½ hours

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE
127th to 130th Reports

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : महोदया, मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं : -

(1) व्यवसाय को सुकर बनाए जाने के संबंध में समिति के 122वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 127वां प्रतिवेदन।

(2) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016-17) के संबंध में समिति के 126वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 128वां प्रतिवेदन।

(3) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016- 17) के संबंध में समिति के 125वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों / टिप्पणियों के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 129वां प्रतिवेदन।

(4) बदलते वैश्विक परिदृश्य में औद्योगिक नीति के बारे में 130वां प्रतिवेदन।

…(व्यवधान)

12.05 hours

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 71st and 88th Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on the `Functioning of Central Government Health Scheme (CGHS)', pertaining to the Ministry of Health and Family Welfare*

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 71st and 88th Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on the 'Functioning of Central Government Health Scheme (CGHS)', pertaining to the Ministry of Health and Family Welfare.

… (*Interruptions*)

* Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 5603/16/16.

12.06 hours

OBSERVATION BY THE SPEAKER
Extension of time to inquiry committee to inquire into the improper conduct of Shri Bhagwant Mann, MP

HON. SPEAKER: Hon. Members may recall that the Committee to Inquire into the Improper Conduct of a Member constituted by me were to submit their Report by 02 December, 2016.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have since received a request from the hon. Chairperson of the Inquiry Committee requesting for further extension of time of one week to present their Report.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: On due consideration of grounds and reasons stated, I have acceded to the request for extension of one more week time and the Committee may present their Report by Friday 09 December, 2016.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: As earlier observed by me, in view of the seriousness of the matter Shri Bhagwant Mann, MP is further advised not to attend the sitting of the House until a decision is taken in the matter.

12.08 hours

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): On behalf of Shri S.S. Ahluwalia, Madam Speaker, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 05th of December, 2016 will consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper:- (It contains consideration and passing of (a) The Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2016 as passed by Rajya Sabha (b) The Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Bill, 2016, and (c) The Mental Healthcare Bill, 2016, as passed by Rajya Sabha.)
2. Consideration and passing of the Surrogacy (Regulation) Bill, 2016.
3. Consideration and passing of the following Bills after they are passed by Rajya Sabha:-
    (a) The Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Bill, 2014.
    (b) The Rights of Persons with Disabilities Bill, 2014.
4. Discussion and Voting on:-
    (a) Second Supplementary Demands for Grants (General) for 2016-17.
    (b) Demands for Excess Grants (General) for 2013-14.
5. Consideration and agreeing to the amendments made by Rajya Sabha in the Enemy Property (Amendment and Validation) Bill, 2016 as passed by Lok Sabha, after it is passed by Rajya Sabha—to replace an ordinance.

HON. SPEAKER: Now, Submissions by Members.

Dr. Kirit P. Solanki – not present.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Mullappally Ramachandran to make his submission. Are you giving?

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No.

Now Prof. Chintamani Malviya.

प्रो.चिंतामणि मालवीय (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदया, मैं अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नांकित लोक महत्व के विषय को सम्मिलित करने का निवेदन करता हूं:-

देश में मुस्लिम आबादी लगभग 20 करोड़ है, जो कई यूरोपीय देशों की कुल आबादी से ज्यादा है, लेकिन भारत में फिर भी उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। फिर भाषाई अल्पसंख्यक का प्रश्न भी उलझा हुआ है।

चूंकि अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं अपने विशेष स्टेटस के कारण शिक्षा के अधिकार के तहत गरीबों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं देती हैं, जिससे शिक्षा का अधिकार कानून को लागू करने में परेशानी आती है।

अत: अल्पसंख्यक शब्द को फिर से परिभाषित करने हेतु सदन में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। कृपया इस महत्वपूर्ण विषय को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में चर्चा हेतु रखा जाए।

खाड़ी देशों की जेलों में बन्द भारतीय मूल की महिलाओं की स्थिति को जानने, उनकी रिहाई हेतु संबंधित मदद मुहैया कराने तथा संबंधित दूतावास को रिहाई संबंधी उचित निर्देश देने हेतु चर्चा कराने बाबत।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में मेरे निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाएः …(व्यवधान)

1. झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर एनएच पर यमुना नदी पर बने पुराने (कालपी पुल) के क्षतिग्रस्त हो जाने के पश्चात् आवागमन में आ रही समस्याओं के संबंध में।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर कालपी नगर में एनएच पर ओवरब्रिज न होने के कारण स्कूली बच्चों की दुर्घटनाओं में मृत्यु तथा अन्य दुर्घटनाओं के संबंध में। … (*Interruptions*)

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में मेरे निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाएः ...(व्यवधान)

1. लखीमपुर नगर के बीच गुरूनानक स्कूल जो लखीमपुर-सीतामार्ग को खीरी- लखीमपुर मार्ग से जोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा नहर के दोनों तरफ बनाया गया है, उसको प्रयोग करने के लिए नहर के एक तरफ बैरियर सं. 148 है लेकिन दूसरी तरफ रेलवे का बैरियर न होने के कारण दूसरी तरफ के मार्ग का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। अतः दूसरी तरफ भी रेलवे का बैरियर लगाया जाए।

2. 1 अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक व कर्मचारियों की पेंशन जो भारत सरकार द्वारा सन 2005 में समाप्त करने का प्रावधान किया गया है, को पुनः शुरू किया जाए तथा 1 अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त सभी शिक्षकों व कर्मचारियों को उसका लाभ दिया जाए।

***श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) :** अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में मेरे निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाएः ...(व्यवधान)

1. बिहार राज्य में भयंकर बाढ़ से प्रभावित व क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अविलंब पर्याप्त धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

2. बिहार राज्य के बांका संसदीय क्षेत्र के अधीन सुल्तानगंज-देवघर एवं मंदार पर्वत को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु स्वीकृत 50-50 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में मेरे निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाएः ...(व्यवधान)

1. मेरे संसदीय क्षेत्र रांची जिले की नामकुम सेना छावनी पास स्थित सुगनू, खटंगा, गाड़ी होटवार, लालगंज एवं नामकुम के निवासियों/आदिवासियों को सुख सुविधा से सेना के जवानों द्वारा वंचित किया जा रहा है एवं तंग किया जा रहा है, उनका रास्ता रोका जाता है गांव की सड़कों को बनने नहीं देते, तालाब, स्कूल जाने में रुकावट डाली जाती है इन सब कारणों से उपरोक्त क्षेत्र के नागरिक अधिकारों का उपयोग करने नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण यहां के लोग, आन्दोलन के मूड में हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस संबंध में सांसदों की एक टीम को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल भेजा जाने का कार्य।

---

* Laid on the Table.

2. मेरे गृह राज्य झारखंड में चांडिल बहुउद्देशीय परियोजना 30 साल से अधिक समय से चल रही है परन्तु इस योजना से प्रभावित अधिकांश विस्थापित परिवार को मुआवजा, विकास पुस्तिका, आवास एवं रोजगार अभी तक नहीं मिला है जिसके कारण विस्थापित परिवार लोगों को कई सालों से लगातार परेशानी हो रही है। चांडिल बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित विस्थापित परिवार को नियमानुसार समुचित मुआवजा, आवास, विकास पुस्तिका, रोजगार एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य।

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन - उपस्थित नहीं।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदया, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नांकित दो विषयों को सम्मिलित किया जाएः ...(व्यवधान)

1. महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के सचिव द्वारा केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव को पिछड़े वर्ग के लिए केन्द्र की ओर से वर्ष 2001-02 से वर्ष 2013-14 तक के बीच की अवधि की बकाया 1392.61 करोड़ की रिम्बर्समेंट राशि को जारी किए जाने हेतु प्रस्ताव भेजे गए हैं और उक्त राशि को जारी किए जाने हेतु 29 रिमाईंडर लेटर भी प्रेषित किए हैं। लंबित बकाया को शीघ्र जारी किए जाने से संबंधित विषय।

2. महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग द्वारा दिनांक 27.8.2013 एवं 23.12.2013 में केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को ग्रेटर मुंबई के सीआरजेड. के अधीन क्षेत्रों में झुग्गी पुनर्वास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश में संशोधन हेतु प्रस्ताव भेजा था और इस बारे में राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव के साथ दिनांक 7.11.2013 में चर्चा भी की थी। केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के नोटिफिकेशन दिनांक 6.1.2011 में संशोधन किए जाने से संबंधित विषय। ...(व्यवधान)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए।

1. अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशनों को जनहित को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाए।
2. भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का देहांत मुम्बई में हुआ था उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप उनको साबरमती नदी के किनारे पंच तत्व में विलीन किया गया था। उस अभय घाट का विकास किया जाए।

...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : माननीय अध्यक्ष जी, एनजीटी ने फैसला लिया है कि अब सारी पेटिशन अंग्रेजी में स्वीकार की जाएंगी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरा मानना है कि यह संविधान की भावना के प्रतिकूल है और राजभाषा, जिसके लिए सदन और सरकार हमेशा प्रतिबद्धता दिखाती रही है, उसके भी विरुद्ध है। ...(व्यवधान) एनजीटी न सिर्फ राजभाषा में काम करे बल्कि स्थानीय भाषाओं को भी अनुमति देनी चाहिए, न कि उसे यह कहना चाहिए कि सिर्फ अंग्रेजी में पेटिशन सुनी जाएंगी। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि एनजीटी से इस बारे में संवाद करे कि वह राजभाषा को ध्यान में रखे और स्थानीय भाषा में पेटिशन स्वीकार करे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री रवीन्द्र कुमार जेना, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,श्री निशिकान्त दुबे, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री गोपाल शेट्टी, डॉ. किरीट पी. सोलंकी और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): माननीय अध्यक्ष जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहां की अधिकतम आबादी सेमी अर्बन ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। सेमी अर्बन ग्रामीण क्षेत्र के विकास और उत्थान हेतु कोआपरेटिव एक्ट के तहत कोआपरेटिव बैंकों की स्थापना हुई।...(व्यवधान) कई कोआपरेटिव बैंक 100 सालों से अच्छी सेवाएं दे रहे हैं और कई बैंकों ने मल्टीस्टेट दर्जा भी हासिल किया है। सांसद कोष को नेशनलाइज्ड बैंकों में रखने का प्रावधान है। आज की तारीख कोआपरेटिव बैंक कोर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, यहां सरकार का पैसा और सांसद कोष रखा जाए इससे पैसे का सुयोग्य संचालन होगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय सदस्य प्रहलाद पटेल जी ने जो प्रश्न उठाया है, मैं इस विषय में उनकी भावनाओं के साथ अपनी भावनाएं जोड़ते हुए सहयोग प्रदान करता हूं। ...(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों विकास के लिए और कानूनी व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित हो, मैं इस विषय में कहना चाहता हूं कि देश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई थी, जिसका नाम आईएपी यानी इंटीग्रेटिड एक्सेल प्लान था। ...(व्यवधान) बाद में इस योजना का नाम बदलकर एसीए यानी एडीशनल सैंट्रल

असिस्टेंस कर दिया गया। इस योजना के तहत विकास कार्य होते थे और नक्सल समस्या को कम और नियंत्रित करने में सहायता मिलती थी। वर्तमान में इस योजना को बंद कर दिया गया है। ...(व्यवधान)

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को योजना चलाने के लिए कहा है लेकिन राज्य सरकारों ने ऐसी कोई योजना नहीं चलाई है। मेरे संसदीय क्षेत्र के औरंगाबाद और गया जिला नक्सलवाद से प्रभावित हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री निशिकान्त दुबे और भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे दिल्ली की एक गंभीर समस्या, सेंसिटिव मुद्दा उठाने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान) दिल्ली में बच्चे स्कूल जाते हैं। ...(व्यवधान) सुबह साढ़े छः बजे बिजली काट दी जाती है, जिससे मां-बाप बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। ...(व्यवधान) दिल्ली में पानी चार-चार दिन नहीं आता। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आज बगैर नहाये हाउस में आया हूं। ...(व्यवधान) दिल्ली में पानी की व्यवस्था नहीं है। ...(व्यवधान) दिल्ली का ...* मुख्यमंत्री पंजाब में अपना टाइम खराब कर रहा है। ...(व्यवधान) वह यहां पर नोटबंदी के खिलाफ ...* कर रहा है। ...(व्यवधान) दिल्ली में पीने का पानी नहीं है। ...(व्यवधान) चूंकि दिल्ली एनसीआर में शामिल है। ...(व्यवधान) यहां सड़कों पर गड्ढ़े हैं। ...(व्यवधान) सरकार इंटरफियरेंस करे। ...(व्यवधान) दिल्ली का मुख्यमंत्री ...* है। ...(व्यवधान) उसकी टीम के पास कोई ...* नहीं है और वह ...* बना हुआ है। ...(व्यवधान) दिल्ली की जनता भुगत रही है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मेरा निवेदन है कि अगर सांसद के इलाके में पानी नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गरीब लोगों को कैसे पानी मिलता होगा? ...(व्यवधान) सर्दी के मौसम में पानी नहीं है, तो गर्मियों में दिल्ली की क्या हालत होगी?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से यह मांग उठाना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरो प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

---

* Not recorded

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Thank you, Madam Speaker. … (*Interruptions*) In our East Godavari District of Andhra Pradesh, ONGC pipelines have been running through 123 villages. … (*Interruptions*) A number of gas leakage incidents, including blow-outs, took place in these villages causing irreparable loss to men and material. … (*Interruptions*) Absence of protective mechanism and timely maintenance of these pipelines is causing untoward incidents and leading to casualties in large numbers in these villages. … (*Interruptions*) Even though, dehydration units are established, the maintenance is so poor. … (*Interruptions*) A small human error costs lives of the people. … (*Interruptions*)

Hence, I would request the hon. Minister for Oil and Natural Gas to instruct the officers of ONGC, East Godavari to always be attentive towards maintenance; install the best-in-class equipment; and rule-out untoward incidents in the future. … (*Interruptions*) Thank you, Madam. … (*Interruptions*)

श्री आलोक संजर (भोपाल) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं भोपाल से आता हूं और मैंने उस गैस त्रासदी के दर्शन किये हैं। …(व्यवधान) उस पीड़ा को मैंने भी भोगा है।…(व्यवधान) आज हम सबने गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी दी है, लेकिन आज भी वहां जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, वे बीमारियों से ग्रसित हैं। …(व्यवधान) जो पुराने लोग हैं, वे भी आज उस पीड़ा को भोग रहे हैं। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री ने वहां दौरा किया था। …(व्यवधान) उस स्थान पर अभी भी जहरीला कचरा उपस्थित है। …(व्यवधान) उसके निष्पादन की कार्रवाई शीघ्र अतिशीघ्र हो। …(व्यवधान) इसके साथ मेरा यह भी आग्रह है कि भोपाल मेमोरियल अस्पताल, जो गैस पीड़ितों के लिए बनाया गया था, उसकी आज बहुत दुर्दशा है। …(व्यवधान) उस दुर्दशा से उसे बाहर निकालने के लिए मैं आज सदन से आग्रह करता हूं। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि वहां रिक्त भूमि पर एक तरफ स्मारक बनाया जाये और शेष भूमि पर गैस पीड़ित लोगों के परिवारों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाये। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरो प्रसाद मिश्र को श्री आलोक संजर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : अध्यक्ष महोदया, बागपत के गन्ना किसानों का पिछले वर्ष का बकाया …(व्यवधान) उमेश मोदी की दो मिलों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। …(व्यवधान) उनके लगभग 340 करोड़ रुपया बाकी हैं। वहां के किसान अभी धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। …(व्यवधान) हजारों लोगों ने 25 तारीख को दिल्ली के संसद मार्ग पर प्रदर्शन किया। …(व्यवधान) अभी एक मिल बंद है। जब तक किसानों का गन्ना नहीं जायेगा तब तक वे गेहूं की फसल नहीं बो सकते। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सबसे पहले दूसरी मिलों के सैंटरों को उनका गन्ना देने का प्रावधान किया जाये। …(व्यवधान) दूसरा, उनका पिछले साल का जो 340 करोड़ रुपया बकाया है, उसका भुगतान करने के लिए यू.पी. सरकार पर दबाव डाला जाये या भारत सरकार शुगर डेवलपमैंट फंड से करे। …(व्यवधान) किसानों के अकाउंट में शुगर डेवलपमैंट फंड से डायरेक्ट पैसा दिलवाया जाये। …(व्यवधान)

तीसरा, भारत सरकार का एक आदेश 1966 का है, जिसे हम केन कंट्रोल आर्डर, 1966 कहते हैं। …(व्यवधान) उसके तहत अगर सरकार किसानों के गन्ने का पैमेंट 14 दिनों तक नहीं करती है या मिल मालिक नहीं करते हैं, तो उसमें 15 परसेंट ब्याज दिया जाये। …(व्यवधान) लेकिन मिल मालिकों ने बैंकों से जो कर्ज लिया था, उसका ब्याज यूपी सरकार ने माफ कर दिया है। …(व्यवधान) लेकिन किसानों से ब्याज लिया जाये, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय यू.पी. सरकार ने लिया है। भारत सरकार इसको देखे। …(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस मिल के मालिक उमेश मोदी के खिलाफ कार्रवाई हो। उसने 231 करोड़ रुपये का घपला किया है। …(व्यवधान) किसानों का पैसा लेकर दूसरी कंपनियों में लगाया है। …(व्यवधान) मैंने उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट एवं एफआईआर दी है, उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके, उसे गिरफ्तार किया जाए।…(व्यवधान) उसकी जितनी भी कंपनीज हैं, उनको सील किया जाए, ताकि वह दबाव में आकर गन्ना किसानों का भुगतान करे। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं डॉ. किरिट पी. सोलंकी को डॉ. सत्यपाल सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, I want to draw the attention of the House to a very important issue.

A massive debit card fraud in major Indian banks such as HDFC Bank, ICICI Bank, YES Bank, Axis Bank and State Bank of India has been reported with

the biggest ever financial data breaches in India. Several victims have reported unauthorized transactions that originated in China and also in the United States, in such frauds. … (*Interruptions*)

The National Payments Corporation of India has ordered an inquiry in the hacking of approximately 3.2 million debit cards across the country. However, the hacking of debit cards on such a large scale has brought the Government and the banking security measures into question. … (*Interruptions*)

I would also mention here that the breach is said to have originated in malware introduced in the system of Hitachi Payment Services, allowing them to steal funds. Hitachi provides ATMs, Points of Sale and other services. Forensic audit has now been ordered by Payment Council of India of Indian banks' servers and system to detect the origin of frauds that might have hit the customers' accounts. … (*Interruptions*)

It is being said that around Rs. 10 crore has been siphoned off, but this is only pertaining to the allegation or what has been reported by the customers. It may be much more which has not been reported yet. Here lies the problem that our security mechanism in banking system has been hacked, and money has been transferred. This gives a very serious turn to the cashless mechanism that you are going to have. Unless our system is surrounded by a firewall, it cannot protect our system. … (*Interruptions*)

A forensic audit is being conducted, Madam. But I would like to understand from the Government or let the Government come back to this House with a full report relating to the forensic audit, and what steps the NPCI has taken in this regard. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Nishikant Dubey, Shri Dushyant Chautala, Shri Dushyant Singh, Shri Sharad Tripathi, Shri Bhairon Prasad Mishra, Dr. Kirit P. Solanki and Shri Rabindra Kumar Jena are permitted to associate with the issue raised by Shri Bhartruhari Mahtab.

… (*Interruptions*)

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बैतूल) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहती हूं। …(व्यवधान) इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में अनेक बड़े फैसले किए हैं, जैसे फसल बीमा योजना।…(व्यवधान) मेरा संसदीय क्षेत्र किसान बहुल है, आज वहां किसानों के पास बैतूल का बड़ा वन क्षेत्र है और किसानों के पास स्वदेशी नस्ल की गाय हैं, जिससे इस क्षेत्र में दूध का उत्पादन अच्छा हो रहा है।…(व्यवधान) साथ ही कृषक खेतों की उर्वरक शक्ति का गोबर खाद के माध्यम से भरपूर उपयोग भी कर रहे हैं। इस क्षेत्र में वन परिक्षेत्र बहुत बड़ा है, जिससे भरपूर मात्रा में हरा चारा भी कृषकों को उपलब्ध हो जाता है। …(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करती हूं कि मेरे क्षेत्र में राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केन्द्र (एनकेबीसी) की स्थापना की जाए, ताकि इस क्षेत्र के पशुओं की देशी नस्ल में सुधार व संरक्षण में कृषकों को सुविधा प्राप्त हो।…(व्यवधान) केन्द्र स्थापना हेतु जिले में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।…(व्यवधान)

अतः मैं आपके माध्यम से यही अनुरोध करती हूं कि बैतूल, हरदा और हरसूद जिलों में राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केन्द्र (एनकेबीसी) स्थापित करें, ताकि इस क्षेत्र के कृषकों को इस प्रोजेक्ट का लाभ प्राप्त हो सके।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं श्री सुधीर गुप्ता को श्रीमती ज्योति धुर्वे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा एवं चित्रकूट जनपद सहित पूरे बुंदेलखंड में अवैध खनन बड़ी मात्रा में हो रहा है। रोज हजारों टन बालू नदियों से निकाली जा रही है। इससे नदियों की धारा बदल गयी है। …(व्यवधान) इसके फलस्वरूप सिंचाई परियोजनाएं फेल हो रही हैं। बुंदेलखंड एक ऐसा ही सूखा प्रभावित क्षेत्र है और वर्षों से हताश एवं परेशान है।…(व्यवधान) अवैध खनने से करोड़ों रुपये की रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है। स्थानीय प्रशासन खनन माफियाओं के दबाव में मूक दर्शक बना हुआ है और इस अवैध कारोबार में सहयोग कर रहा है। हालत बहुत ही गंभीर है। आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस अवैध खनन पर अंकुश लगाने के पर्याप्त उपाय यथाशीघ्र किये जाएं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री जनक राम - अनुपस्थित।

श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान पनियाहवा से टमकुही रेल मार्ग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने शिलान्यास करके योजना की शुरुआत की थी।...(व्यवधान) 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी, पिछले साल जब मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 5 करोड़ रुपया दिया गया था और पिछले सत्र में 2016-17 में 20 करोड़ रुपया दिया गया है।...(व्यवधान) लेकिन अभी तक उस कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस काम को यथाशीघ्र चालू करवाया जाए। यह मध्य रेलवे में पड़ता है। मैं जोन कमेटी का मैम्बर नहीं हूं।...(व्यवधान) हमें उस कार्य योजना के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है जबकि रेलवे लाइन मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर जाती है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसकी पूर्ण जानकारी मुझे मिलनी चाहिए और कार्य में प्रगति होनी चाहिए और मुझे इस कमेटी का मैम्बर भी होना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सतीश चन्द्र दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भगवान गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान पाली भाषा में दिया है।...(व्यवधान) मैं सरकार से अनुरोध एवं मांग करता हूं कि हमारे देश में औरंगाबाद, मराठवाड़ा में अजंता गुफाओं के पास अन्तर्राष्ट्रीय पाली यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाए।

देश विदेश के छात्र पाली भाषा का ज्ञान लेने के लिए हमारे देश में आते हैं। एक स्वतंत्र पाली यूनिवर्सिटी की स्थापना केन्द्र सरकार करे, यह अनुरोध मैं आपके माध्यम से सरकार से करता हूं।...(व्यवधान) औरंगाबाद में डा. बाबासाहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी में परिवर्तित करने की भी मांग मैं आपके माध्यम से करता हूं। धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Hon. Speaker, tomorrow is the World Disability Day. We are entering the tenth year of the UN Convention on Rights of People with Special Ability. We have the 21st year of our own Disability Act since 1995. In our country, we have not got a single vocational institute dedicated to the skill training of people with special abilities. While we give reservations and some opportunities to them, but the modules, the special

educators and special teachers are not available for their skilling. Because of that, when they compete in the job market, they are not able to compete completely. Though they get certificate yet their skilling is not enough. … (*Interruptions*)

The second aspect is that our special people with special abilities have won two Gold, one Silver and one Bronze Medals in Paralympics. But we have not a single sport centre dedicated to people with special abilities. So, they have achieved everything, which is available to them, on their own courage and because of their own grit. But insofar as facilities and Government mechanism are concerned, there is nothing much. The areas are managed by District Magistrates and IAS officers. While the Academy teaches them close to 400 Acts, but in their curriculum, the Disability Act is not even taught. My request through you is that the Government should pay attention to these three basic subjects. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Sudheer Gupta, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Sharad Tripathi, Shri Rabindra Kumar Jena, Shri Gajendra Singh Shekhawat and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Meenakashi Lekhi.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बुंदेलखंड के संबंध में बोलने के लिए अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। …(व्यवधान) हमारा बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ है, पूरे देश को यह जानकारी है। …(व्यवधान) भारत सरकार बुंदेलखंड के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देती रही है, …(व्यवधान) लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उसका सदैव दुरुपयोग करती रही है। …(व्यवधान) लगातार 10 वर्षों से वहां सूखा पड़ने के बाद इस वर्ष ईश्वर की कृपा से अच्छी बारिश हुई है और बहुत अच्छी फसल खड़ी है,…(व्यवधान) लेकिन गोवंश के लिए और जानवरों के लिए चारा नहीं होने से लोगों ने अपने सभी मवेशियों को छोड़ दिया है, जो किसानों की फसलों को भयंकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं एक मिनट का समय और लूंगा।…(व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।…(व्यवधान) वैसे ही कांग्रेस के लोगों ने पूरा सत्र …(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि स्पेशल पैकेज के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार को सख्ती से निर्देशित करें कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र

में गोवंश को पालने के लिए गुजरात के पैटर्न पर, जहां प्रत्येक पंचायत में जो कैटल शेड्स बनाये गये हैं, वे बनाये जायें, …(व्यवधान) कम से कम, जब स्पेशल पैकेज दिया जाता है।…(व्यवधान) वहां जानवरों के लिए चारा नहीं है तो गोपालक को एक हजार रूपये प्रति गाय की दर से पैसा दिया जाये,…(व्यवधान) ताकि वहां गायें भी बच सकें। …(व्यवधान) सिक्किम की तरह स्पेशल तरीके से बुंदेलखंड एग्रो-इकोनॉमिक जोन बन सके और किसानों की आमदनी दुगुनी हो सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और भानु प्रताप सिंह वर्मा जी को कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

The House stands adjourned to meet again on Monday, the 5th December, 2016 at 11.00 a.m.

12.37 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 5, 2016/Agrahayana 14, 1938 (Saka).